

This question paper contains 8 printed pages]

Your Roll No.

7937

LL.B./IV Term

E

Paper LB-402

ADMINISTRATIVE LAW

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :— Answers may be written *either* in English *or* in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt *five* questions in all.

All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (a) "Our Constitution is modelled on the British Parliamentary System, where the executive function comprises both the determination of the policy as well as carrying it into

P.T.O.

execution.” The Executive Government of a state formulates a particular policy in furtherance of which they want to start a trade or business. Is it necessary that there must be a specific legislation legalising such trade activities before they could be embarked upon ? Decide with the help of relevant case law.

- (b) Discuss the importance and source of ‘right to information’. Whether the contents of declaration of assets by the judges to the Chief Justice of India amount to personal information and therefore are exempt under Section 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005. 20

- (a) “हमारा संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के मॉडल पर बना है जहाँ कार्यकारी कार्य में दोनों नीति का निर्धारण तथा साथ ही उसका निष्पादन किया जाना समाहित है।” किसी राज्य की कार्यकारी सरकार कतिपय नीति का सूत्रपात करती है जिस पर आगे कार्य करते हुए वह कोई व्यापार अथवा कारबार शुरू करना चाहती है। क्या यह आवश्यक है कि ऐसी व्यापार गतिविधियों को शुरू किए जाने से पूर्व उनको विधिसम्मत बनाते हुए एक विशिष्ट विधान का होना अनिवार्य है ? सुसंगत निर्णय विधि की सहायता विनिश्चय कीजिए।

- (b) 'सूचना के अधिकार' के महत्व और स्रोत का विवेचन कीजिए। क्या न्यायाधीशों द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को की गई आस्तियों की घोषणा की अन्तर्वस्तु वैयक्तिक सूचना के समान है, अतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।
2. (a) Distinguish between 'power of modification' and 'power to remove difficulties'.
- (b) Whether power to levy taxes for the 'Purpose of the Act' is valid delegation of power ? 20
- (a) 'उपान्तरण की शक्ति' और 'कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति' के बीच भेद सुस्पष्ट कीजिए।
- (b) क्या अधिनियम के प्रयोजन हेतु कर उद्ग्रहण करने के लिए शक्ति शक्ति का वैध प्रत्यायोजन है ?
3. A State Legislation reads :
- "The rules as sanctioned by the State Government shall be published by the municipality in the municipal borough and shall be laid before the State Legislature as soon as may be, after it is made."

The State Government approved certain rules by which municipal taxes were sought to be levied by a municipality. The notice published by the municipality merely stated that "the rules can be inspected at the office of the municipality on all working days during office hours."

A house owner was called upon to pay tax in respect of his house. He challenged the imposition of the tax on the ground that the rules were neither published as required nor laid before the legislature. Decide giving reasons. 20

किसी राज्य के विधान का पाठ इस प्रकार है :

“राज्य सरकार द्वारा मंजूरशुदा नियमों को नगरपालिका द्वारा नगरीय क्षेत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा ऐसा किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।”

राज्य सरकार ने कतिपय नियमों को अनुमोदित किया जिनके द्वारा नगरपालिका द्वारा नगरपालिका कर उदग्रहीत करने का प्रयास किया गया। नगरपालिका द्वारा प्रकाशित नोटिस में मात्र यह उल्लिखित था कि नियमों की सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय

समय में नगरपालिका के कार्यालय में जांच की जा सकती है।”

किसी गृह स्वामी को अपने घर के बारे में कर भुगतान करने के लिए कहा गया। उसने इस आधार पर कराधरोपण को आक्षेपित किया कि नियमों को अपेक्षानुसार न तो प्रकाशित किया गया, न विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सकारण विनिश्चय कीजिए।

4. “The principle of primary review and proportionality on the one hand and the principle of secondary review and *wednesbury* reasonableness on the other hand gave a new dimension to Administrative Law, the former applying in the case of fundamental freedoms and the latter, in other cases.”

Discuss referring to decided cases.

20

“एक ओर प्राथमिक पुनर्विलोकन और समानुपातिकता के सिद्धान्त ने और दूसरी ओर द्वितीय पुनर्विलोकन और वेडनसबरी युक्तियुक्तता के सिद्धान्त ने प्रशासनिक विधि को नए आयाम प्रदान किए थे—इनमें से पहले वाला मूल स्वतंत्रता पर और बाद वाला अन्य मामलों पर लागू होता था।”

विनिश्चित कसों को निर्दिष्ट करते हुए विवेचन कीजिए।

5. (a) The dichotomy between administrative and quasi-judicial proceedings *vis-a-vis* the doctrine of natural justice was finally discarded as unsound by the Supreme Court in A.K. Kraipak *Vs.* Union of India. Discuss.

(b) Decide, in the light of case law, whether the following action is valid :

X, a member of selection committee, interviews Y whose confidential report was written by him, wherein he expressed appreciation of work of Y. . 20

(a) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के मुकाबले में प्रशासनिक और अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों के बीच द्विविभाजन को उच्चतम न्यायालय द्वारा A.K. Kraipak *Vs.* Union of India केस में विकृत बताकर अंतिम रूप से नकार दिया गया था। विवेचन कीजिए।

(b) निर्णय विधि को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय कीजिए क्या निम्नलिखित अनुयोग्य विधिसम्मत है :

चयन समिति का सदस्य X उस Y का साक्षात्कार करता है जिसकी गोपनीय रिपोर्ट उसी ने लिखी थी जिसमें उसने Y के कार्य की सराहना की थी।

6. Discuss the scope and importance of *maxim audi alteram partem* in administrative adjudicatory process with the help of judicial pronouncements relevant to the subject. Explain why when the hearing is obligatory, the extent of hearing varies from case to case. 20

प्रशासनिक न्याय-निर्णयन प्रक्रिया में दूसरे पक्ष को भी सुनो सूक्ति की परिव्याप्ति और महत्व को इस विषय से सुसंगत न्यायिक उद्धोषणाओं की सहायता से विवेचित कीजिए। स्पष्ट कीजिए जब सुनवाई बाध्यकर है तब उसकी विस्तृति केस दर केस भिन्न क्यों हो जाती है ?

7. (a) Can the High Court while exercising its writ jurisdiction review finding of fact recorded by administrative tribunals ?
- (b) Can be writ of *Mandamus* be issued to the governing body of a private college, affiliated to a State University to enforce conditions of service of its teachers ? 20
- (a) क्या उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा रिकार्डिड तथ्य के निष्कर्ष का पुनरावलोकन कर सकता है ?
- (b) क्या अध्यापकों की सेवा शर्तों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राइवेट कालिज के शासी निकाय को परमादेश रिट जारी की जा सकती है ?

8. Write short notes on any *two* of the following : 20

- (a) Advantages offered by Administrative Tribunals.
- (b) Distinguish between 'Judicial Review' and 'Appeal'.
- (c) '*Malafide* exercise of power' as a ground of Judicial Review over administrative discretion.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा दिए गए लाभ।
- (b) 'न्यायिक पुनर्विलोकन' और 'अपील' के बीच भेद सुस्पष्ट कीजिए।
- (c) प्रशासनिक विवेकाधिकार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार के रूप में अधिकार का असद्भावपूर्वक प्रयोग।